



E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2022; 4(2): 01-03
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 03-04-2022
Accepted: 04-05-2022

Dr. Beena Joshi
Assistant Professor, Political
Science, Govt. Girls College,
Haldwani, Uttarakhand, India

गंगास नदी की मरती सहायक धाराएँ

Dr. Beena Joshi

सारांश

दुनिया भर में मरती नदियों के पीछे कारण बढ़ता शहरीकरण तथा घटते गांव है। विकसित तथा विकासशील सभी देशों ने अपनी नदियों को पिछले 20 वर्षों में खोया है। पानी की मात्रा तथा गुणवत्ता का नुकसान आज दिखाई दे रहा है। शहरों का कचरा ढोती नदियां मरने के कगार पर है। यही हाल ग्लेशियरों का भी है। जलवायु परिवर्तन से बढ़ता तापमान ग्लेशियरों पर हमला कर रहा है। शहरों की बढ़ती बिजली, पानी की आवश्यकता गांव के हिस्से को लील चुकी है। जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभाव हिमालय पर पड़ा है। भारतीय हिमालय यूवा है लेकिन विश्व स्तर पर हिमालय क्षेत्र के बारे में बहुत कम ध्यान गया है। पृथ्वी की सभी भागों की पीड़ा को समझना होगा। नये-नये आविष्कार पहले से ठाठ से जी रही जनता को तुष्ट करने में लगी है। जबकि बड़ी आबादी मौलिक आवश्यकताओं से वंचित है। उत्तराखण्ड में राज्य संरक्षित खनन ने नदियों और पहाड़ों के अस्तित्व को खतरों में डाल दिया है। सदाबहार नदियां दम तोड़ने लगी है तथा जलचक्र प्रभावित है। नन ग्लेशियर पर नदियों पर छोटे-छोटे खाव बनाकर जीवनदान देना होगा। पश्चिमी दर्शन इस्तेमाल करें और फेंको की नीति की जगह पर्यावरण समर्थित भारतीय दर्शनवाली जीवनशैली अपना ली होगी। जागरूकता और जनसहभागिता से सफलता मिलेगी न कि केवल कागजी सरकारी योजनाओं से। कभी सदा बहने वाली गंगास नदी की आज 95 प्रतिशत धाराएँ सुख गई है जो अन्तिम सांसे गिन रही है। पानी बचाने की नहीं पानी उगाने की मुहिम छेड़नी है। नदी, पर्यावरण व जंगल में सामंजस्य बिठाना है विस्तृत शोध में परिकल्पना के समस्या के कारणों, प्रभावों, समाधानों को खोजने का प्रयास किया है।

मूल शब्द: बढ़ता शहरीकरण, विकसित देश कानून, पानी की मात्रा तथा गुणवत्ता का नुकसान

प्रस्तावना

भारत ने विकास की अवधारणा भले ही पश्चिम से ले ली लेकिन इसमें पर्यावरण को जगह नहीं दी। विकसित देश कानून द्वारा विकास व पर्यावरण में संतुलन बनये रखते हैं जबकि भारत में कंकरीट व डामर का घोल। परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि। गर्मी में ज्यादा गर्मी, ठण्डे में ज्यादा ठण्ड। पेड़, घास, झाड़िया तथा मिट्टी सूर्य के ताप को अपने में समा लेती है। जिससे जमीन ठण्डी रहती है जबकि कंकरीट केन्द्रित विकास ने जंगल, नदी, व कृषि को समाप्त किया है। पानी के प्राकृतिक स्रोत सूखते जा रहे हैं।

‘खनन’ ने नदी व पहाड़ के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। जिसे राजीतिक संरक्षण प्राप्त होता है जलस्रोत सूखने के कारण जानवरों को मजबूर होकर पानी पीने के लिए बाहर आना पड़ता है। उत्तराखण्ड के अलग-अलग इलाकों में भूख व प्यास के कारण जानवरों की गांवों में घुसने की घटनाएँ आती हैं। कारण है पानी की तलाश। पेड़ की कटाई व खनन ने जलवायु चक्र की पूरी व्यवस्था को खत्म कर दिया है। पानी को संजोकर रखने वाले परम्परागत वृक्षों की संख्या घटती जा रही है। प्रशासन कोई ऐसी नीति नहीं अपनाती जो परंपरागत जलस्रोतों को विकसित कर सकें। बदलती दुनिया ने हमारे पर्वतीय गांव कमजोर पड़ते जा रहे हैं। यूनेस्को की एक रिपोर्ट के अनुसार 1945 में गांवों की आबादी 3 अरब थी शहरों की लगभग 2 अरब। 2015 आते-अउते गांवों की आबादी 2 अरब तथा शहरों की आबादी 3 अरब से अधिक हुई है। दुनिया में मरती नदियों का कारण बढ़ता शहरीकरण तथा घटते गांव है। पानी की मात्रा व गुणवत्ता का बड़ा नुकसान हुआ है। शहरों का कचरा ढोती नदियों की तरह ग्लेशियरों की भी ऐसी ही स्थिति है। ग्लोबल वार्मिंग सर्वप्रथम इन्हीं पर हमला कर रही है।

समस्या, कारण व प्रभाव

उत्तराखण्ड के कुमाऊँ में ‘गंगास’ नदी ऐसी है जिसके दो उद्गम स्थान माने जाते हैं कभी सदाबहारी रही नदी अब तेजी से सूखती जा रही है। स्थानीय जनता की समझ व सहयोग के बल पर इसे फिर से सदाबहारी करने का प्रयास अमर उजाला फाउंडेशन द्वारा 22 मई 2017 से किया गया। रानीखेत व आसपास के कस्बों के लिए जीवनदायिनी गंगास नदी को जंगल ही बचाए हुए है।

Corresponding Author:
Dr. Beena Joshi
Assistant Professor, Political
Science, Govt. Girls College,
Haldwani, Uttarakhand, India

गंगास को पानी फीड करने वाले धारपानीधार एक्वीफायर (भूमिगत जलाशय) में पानी कम होने से 43 सालों में गंगास का पानी तेजी से कम हुआ है। 43 सालों में गंगास का पानी तेजी से कम हुआ है। अल्मोड़ा में करीब 52 वर्ग कि०मी० में गंगास नदी का जल संग्रहण क्षेत्र है²। जलाशय का पानी कम होने से इस नदी की कई जलधाराएं अपना अस्तित्व खो चुकी है। रानीखेत सहित अन्य कस्बों के करीब 50,000 लोगों को पानी उपलब्ध कराने वाली गंगास नदी का संकट इन सब लोगों का संकट बन रहा है पानी कम होने का एक कारण 'जंगल की आग' भी है।

कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बंजर जमीन में पानी को सोखने की क्षमता कम होती है। फलस्वरूप रिचार्ज होने की क्षमता कम होगी। हमारे विकास के सारे काम हवा, पानी, जंगल, मिट्टी, आकाश सबको बर्बाद करने पर तुले हैं। सरकार व जनता नदियों को बचाने में असफल रही है। 'अमर उजाला फाउंडेशन' ने जनजागरण कर महत्वपूर्ण काम किया है। जलस्तर निरंतर गिरने से गंगास नदी अंतिम सांसे गिन रही है³। नदी से रानीखेत, द्वााराहाट क्षेत्र के लिए 6 बड़ी पेयजल योजनाएं संचालित हो रही है वहीं क्षेत्र के किसान सिंचाई के लिए भी इसी पर निर्भर है। पिछले 12 सालों में प्रवाह में कमी आया है। नदी की यात्रा चुनौतियों से भरी पड़ी है। गंगास नदी के उद्गम स्थल के पास ही 3 धाराएं मिलती है। नन- ग्लेसियर होने के कारण नदी को रिचार्ज करना जरूरी है।

ग्लोबल वार्मिंग के कारण कुमाऊँ की सरयू, रामगंगा ईस्ट, रामगंगा वेस्ट, नदियों का रूप कैनाल का रूप ले चुकी है। चैक डेम या खाल-चाल (खाव) बनाकर ही इनको जीवन दिया जा सकता है। लोगों द्वारा कचरा फैलाने से ग्लेसियर क्षेत्रों का माइक्रो क्लाइमेट डिस्टर्ब हो जाता है। कचड़ा सड़ने से खतरनाक गैस निकलती है। यही गंदगी बहकर पानी में आती है व ग्लेसियर टूटन बढ़ जाती है⁴।

रेता बजरी के लिए गंगास नदी का सीना छलनी किया जा चुका है। इस पर प्रभावशाली कुछ ग्रामीण लोगों का वर्चस्व है बाकी ग्रामीण बेबस। पानी को बचाने के लिए लोगों को एकजुट करना कठिन काम है। जल संस्थान की ओर से गांव के लोगों को पेयजल योजना ना के बराबर है महिला मंगल दल एक संगठन मतभेदों के कारण सक्रिय नहीं है। गांव से बहती जंतरगाड़ में बजरी पत्थर के लिए खुदाई की जा रही है।

पहाड़ों का विकास होना भी पलायन की एक वजह रही है। सुविधाओं के बाद भी हवालबाग अल्मोड़ा के 50 परिवार पलायन कर गए। उच्च शिक्षा व रोजगार की चाहत से छूट रहा है। गांव जबकि गांव में अदरख, लहसुन, तेजपात की खेती भरकस मात्रा में होती है। आज पहाड़ दहशत में है पानी की कमी मुख्य कारण है।

"जल संघर्ष" गंगास घाटी में पनप रहा है कुकुछीना से नायल तक पानी कम हुआ है। पानी पर अधिकार को लेकर अत्यधिक खींचतान है। दुनागिरी के आस-पास के क्षेत्रों में पानी के लगातार कम होने का असर दिखा है। जो पूरे क्षेत्र में प्रसार रहा है। रतखाल गर्भमुनी के आश्रम, खोलियाबांज, पाण्डुकेश्वर से निकलने वाली धाराएं रतखाल में ही गंगास नदी का रूप ले लेती है। जो खोलिया गांव दुधौती ओर अन्य कई गांवों को पानी देती है इसका पानी कम होता जा रहा है। जो पानी बचा है यही झगड़े की वजह बना है। मंदिर समिति तो पानी का इस्तेमाल तो करती है लेकिन संवर्धन के लिए प्रयान न के बराबर। इस पानी पर गांव का भी हक होता है।

एक व्यवसायी ने बोरिंग कर प्रतिदिन बड़ी मात्रा में पानी का निजी उपयोग शुरू कर दिया। इस पूरे क्षेत्र में सदा बहने वाली 95 प्रतिशत से अधिक की धाराएं सूख गई है। जीवन प्रभावित होने से फसल भी प्रभावित होती है। "सूखी नदी से "लाल गर्मी" पैदा होती है। जो बादलों को दूर भगा देती है⁵। कुकुछीना से

नायल तक पानी का स्तर इतना कम हुआ है कि हर ग्रामसभा में पानी को लेकर विवाद है। कुकुछीना से नायल तक पानी की 95 प्रतिशत धाराएं सूख चुकी है।

समाधान

हम पृथ्वी को माता मानते हैं और सतत विकास हमारे दर्शन व विचारधारा का मूल सिद्धांत रहा है। महात्मा गांधी के शब्दों में "धरती प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता तो पूरी कर सकती है पर प्रत्येक व्यक्ति के लालच को नहीं"⁶।

आज पर्यावरण चिन्तक विकास के नाम पर होने वाले हर तरह के विकास को रोकने को उतारू है जबकि नीतिकार इसे मानने को तैयार नहीं। आज प्रश्न है विकास बनाम पर्यावरण दोनों ही तरह की अतिवादिता से बचना होगा। विकास की सीमा के अन्तर्गत नीति व योजनाएं बनें⁷। उत्तराखण्ड के लिए नये फ्रेमवर्क जरूरी है। उत्तरपूर्वी राज्यों में सफल शोध के बाद सफल तस्वीर सामने आयी है। जिसका उपयोग पूरे हिमालय क्षेत्र में किया जा सकता है।

जंगलों की हरियाली लौटाकर पाईपलाईन सभ्यता की जगह नदी सभ्यता को लेना होगा⁸।

पानी बचाने की नही उगाने की मुहिम छेड़नी होगी ताकि बारिश का पानी गंगास में रह ले⁹। बांज बुराश के पेड़ लगाकर खनन रोकना होगा। पानी, पर्यावरण व जंगल के बीच सामन्जस्य स्थापित कर उमर उजाला फाउंडेशन ने 22 मई 2017 से जनचेतना जागृत कर सराहनीय कार्य किया। जलपुरुष को भी भागीदार बनाया गया। नदी बचाने की शुरुआत गंधेरे बचाकर ही की जा सकती है। फाउंडेशन द्वारा पदयात्रा कराकर लोगों को जागरूक किया गया। खोलियाबरी, रतखाल, नायल, कुकुछीना, अभियांगाव, जंतरगाड़ आदि अनेक गांवों से पदयात्रा गुजरी। परिणाम स्वरूप लोग नदी संरक्षण को आगे आए।

चेतना रैली का प्रभाव यह हुआ कि जल पंचायत ने सूखी नदी के सीने पर जल पंचायत बुलकार चाल-खाल (खाव) बनाने का संकल्प लिया। गांववासियों ने खुद जिम्मेदारी ली। अभी बरसात में यह काम किया गया। 'चीड़ के पेड़ों' से भी छुटकारा पाना जरूरी है। महिलामंगल दल भी इससे जुड़ने लगीं जिसकी अध्यक्ष पार्वती रावत ने स्वयं कमान अपने हाथ में लेकर खाव बनाने की शुरुआत की। "गांव व समाज जुड़ेगा तभी बचेगा पानी"¹⁰। जंतरगाड़ से 3 किमी० नीचे तक नदी में भरपूर पानी है कारण 'पासीखाव' का लबाबल भरा रहना।

आने वाली पीढ़ी के लिए धरती को बचाना होगा पृथ्वी के व्यवहार में बदलाव के कारण भ्रमित सरकार व समाज को जीने का रास्ता याद दिलाना होगा।

उद्देश्य

'गंगास नदी' बीमार है पर आई०सी०यू० में नहीं। नदी का स्वरूप बिगड़ गया है। इसे पुनर्जिवित करना होगा। महिला मंगलदल द्वारा शुरू की गयी किल्मोड़ा, हिसाल, झिंगारू की झाड़ियों को न काटने की परंपरा को जनचेतना का माध्यम से आगे बढ़ाना होगा। बोराखोला गांव में सूखे परंपरागत खाव को जो अब मिट्टी से भर चुका है फिर से बनाकर जीवन देना होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय जलप्रबंधन के अनुसार: करीब 1.2 अरब लोग भौतिक जलसंकट से गुजर रहे हैं। जबकि 27 करोड़ लोग बेहतर जल से वंचित हैं। करीब 25 लाख लोगों की मृत्यु प्रदूषित जल के कारण होती है¹¹। यह स्थिति न हो इस पर ध्यान देना इस लेख का उद्देश्य है।

हमारे विकास के काम हवा, पानी, मिट्टी, को बरबाद कर चुके हैं। 737 प्रजातियां लगभग समाप्त हो गई हैं। 11 प्रतिशत प्रजातियों खतरे के कगार पर हैं। दुनिया की सभी नदियां किसी न किसी

संकट से गुजर रही हैं नदियां जल की मात्रा व गुणवत्ता खो रही है¹²। हमारे देश की 70 प्रतिशत नदियां मरने के कगार पर हैं। इस समस्या की गंभीर मानते हुए –

- गांव के प्रति लोगो की मनः स्थिति में परिवर्तन लाना तथा जल के प्रति जागरूक करना।
- बाज व बुरांश पेड़ उगाने की पर्वतीय क्षेत्रों की संस्कृति का विकास।
- नदी से टैंकरों द्वारा संस्थानों को पानी सप्लाई रोकना उन्हें त्पद भ्तअमेजपदह तकनीक अपनाने को प्रेरित करना।
- 90 प्रतिशत सूखी नदियों को पुनः अध्ययन कर खाल-चाल पद्धति कारगर हुई या नहीं।
- लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया में सरकार पर गांव का लोक नियंत्रण स्थापित कर कमबपेपवद डांपदह में भागीदार बनाना व उसके साथ हो रहे अन्याय का प्रतिकार करना ही इस शोध लोक का उद्देश्य है।

अध्ययन पद्धति

प्रत्यक्ष रूप से इस क्षेत्र से जुड़े रहने के कारण तथा चुनौती का अनुभव का भागीदार होने के कारण मनोविश्लेषणात्मक व्यवहारवादी पद्धति का प्रयोग कर केस स्टडी में पर्यवेक्षात्मक पद्धति काफ़ी अपनाया गया है। तटस्थता का निर्वाह करते हुए, आधुनिक राजनीतिक विकास उपागम का प्रयोग कर गांव के सम्पूर्ण विकास सम्बन्धी समस्याओं को समझने का प्रयास किया गया है। राजनीतिक विकास उपागम से गांव की राजनीतिक समस्याओं का विवेचन, तुलना, स्पष्टीकरण व भविष्यवाणी करने में मदद मिली है।

निष्कर्ष

हिमालय का जल मिट्टी पूरे देश का काम आता है। हिमालय आक्सीजन का भंडार है इसके बावजूद थी पर्वतीय क्षेत्रों की सुध राजनीतिक व्यवस्था को नहीं। पहाड़ के गांव, तकनीक सुविधाओं के अभाव के कारण शहरों की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। जल, जंगल, जमीन के बावजूद पर्वतीय क्षेत्रों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, विकास से वंचित कर पलायन को बढ़ावा देने को विवश गांव समाजिक, आर्थिक राजनीतिक अन्याय को दर्शाता है। सरकार का गांवों के प्रति कोई सरोकार नहीं है। सही नीति नहीं होने के कारण पहाड़ पर भूमाफियाओं का बोलबाला है। नीतियां शहर आधारित बनती हैं। कुशल नेतृत्व की जरूरत है जो निवासियों के मानसिक चेतना जाग्रत कर पहाड़ की महत्ता को बता सके।

संदर्भ

1. यूनेस्को की 2015 रिपोर्ट। इंडिया टूडे।
2. Sustainable development in Mountain- Georgi Zhelozov.
3. जलपुरुष मैगसेसे पुरस्कार से सम्मानित राजेन्द्र सिंह का उमर उजाला को साक्षात्कार मई – 2017
4. डा० समीर तिवारी, गंगोत्री प्रभारी, वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान।
5. जल पुरुष राजेन्द्र सिंह के विचार 'गंगास' सर्वेक्षण पर। अमर उजाला में।
6. महात्मा गांधी के शब्द – My experience with Truth.
7. सुमित्रा महाजन, 1916 लोकसभा भाषण।
8. डा० अनिल जोशी, हेस्को के निदेशक का अमर उजाला को साक्षात्कार।
9. मोहन काण्डपाल, सीड संस्था के संस्थापक
10. हेस्को के संस्थापक अनिल जोशी का हिन्दुस्तान टाइम्स को साक्षात्कार।

11. अन्तराष्ट्रीय जल प्रबन्धन रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्रीय संघ 2017
12. डब्लू०एच०ओ० की रिपोर्ट 2016
13. New aspects of Political Development ल्यू-शियन पाई।
14. मुम्बई मौखिक 2016 (पलायन पर विचार गोष्ठी)
15. अमर उजाला, पद यात्रा गंगास नदी पर 22 मई 2017 से
16. प्रो० लुईस – The Theory of Economic growth.
17. UNO आर्थिक प्रतिवेदन– 2016 Aljazeera
18. Madison, British Economist, Devt. centre Study VI, Millenial Perspective.
19. प्रो० रोस्टोव & The stages of Economic growth.